agree to make a recomendation with regard to creation of a bench of the High Court in the State itself, it is only then, that the proposal can be considered by the Central Government. As of today, as far as Tamil Nadu is concerned, there is a bench being constructed in Madurai; as far as West Bengal is concerned, there is a proposal, which has been accpeted, for creation of a bench in Jalpaiguri. Besides these two, no complete proposal for a bench in regard to any other High Court is pending.

With regard to the public utilities and Lok Adalats, Lok Adalats as a concept, as they have been existing, cover private institutions also. Lok Adalats, which were operating under the original regime, from 1988 onwards, have covered even private parties-matrimonial and other cases; they have been amicably resolved by the Lok Adalats. Therefore, in respect of any public utility, even if it goes into the hands of the private sector, as far as the present Act is concerned, it would have no implication, as far as the Lok Adalats are concerned.

दूरर्शन की आय के लिए निर्धारित लक्ष्य

*87. श्री राम जेठमलानी:

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': †

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003-2004 के दौरान दूरर्शन की आय बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया हैं;

(ख) यदि हां , तो इस लक्ष्य की राशि क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए इस लक्ष्य की कोई राशि निर्धारित की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) वित्तिय वर्ष 2002-2003 के प्रथम नौ महीनों के दौरान दूरदर्शन की कुल आय कितनी थी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ड) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया हैं।

† सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रजंन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया हैं कि दूरदर्शन की आय के वर्ष 2002-2003 के लिए 550 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2003-2004 के लिए 550 करोड़ रुपये लक्ष्य हैं।

(ड) दूरदर्शन ने सूचित किया हैं कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के पहले 9 महीनों के दौरान कुल आय 308.27 करोड़ रुपये हैं।

Target set for earnings of Doordarshan

†*87. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':††

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have set any target in order to increase the earnings of Doordarshan during the year 2003-2004;

(b) if so, the targeted amount;

(c) whether Government have fixed any target amount for the financial year 2002-2003;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the total earnings of Doordarshan during first nine months of the financial year 2002-2003?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Prasar Bharati has informed that the target for earnings of Doordarshan for the year 2003-2004 is Rs. 550.00 crores and for the year 2002-2003 is Rs. 550.00 crores.

(e) Doordarshan has reported that the total earnings during first nine months of the financial year 2002-2003 are Rs. 308.27 crore.

† Original notice of the question was received in Hindi.
†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन": सभापति , महोदय प्रसार भारती में आय कम है और व्यय ज्यादा हैं । सरकार ने अपने उत्तर में कहा हैं कि 2002-2003 में इनकी आय का जो लक्ष्य हैं, वह 550 करोड़ रुपये रखा गया था। नौ महीने में मात्र 308.27 करोड़ रुपये की आय इनकी हुई हैं । जब कि इसी सदन में 23-7-2002 को एक अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर में सरकार ने कहा कि प्रसार भारती के जो कर्मचारी हैं, उनके वेतन पर सालाना 504.48 करोड़ रुपये खर्च होता हैं । इसके अलावा जो इनका इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, उस पर भी खर्च होता हैं । इनकी आय कम हैं और व्यय ज्यादा हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार प्रसार भारती में उसके वित्तीय कुप्रबंधन पर रोक लगाने के लिए और उसको आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या योजना बना रही हैं और उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ललन जी इस बात को समझेंगे कि दूरदर्शन, आकाशवाणी ये पब्लिक ब्राड कास्टिंग एजेंसीज़ हैं । अतः व्ययवसाय, मुनाफा, राजस्व इसका एक मात्र उसूल नही बन सकता हैं ।अन्य चैनल्स का दूसरा दृष्टिकोण होता हैं । मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे हमें एशियन गेम्स दिखाना पड़ा। उस पर हम लोगों ने 11 करोड़ रुपये का खर्चा किया और मात्र 55 लाख रुपया कमाया, क्योंकि इसको दिखाना आवश्यक था। हमने नेशनल गेम्स दिखाया, जहां उस पर पांच करोड़ रुपये खर्च किया, वहां मात्र पांच लाख की आमदनी हुई । अतः सिर्फ मुनाफा ही दृष्टिकोण नहीं हो सकता हैं । लेकिन हां हमें इस बात का प्रबंध करना पड़ेगा कि उचित राजस्व मिले, उनका कंटेट इम्प्रूव हो, इसलिए मैंने स्वयं इसकी बैठक ली हैं , एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई हैं, आज दूरदर्शन का रीच 89 परसेंट हैं । आकाशवाणी को 24 करोड़ लोग देखते हैं । ये जो हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी जनता के बीच में ठीक प्रकार से जायें और और अच्छी माकेटिंग स्ट्रेटजी बने, रिसेप्सन अच्छा बने, मैं इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ।

श्री बालकवि बैरागी: धन्यवाद सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्व के बचाव के लिए या बढ़ाव के लिए आप जो प्रयत्न करते हैं , प्रसार भारती प्रयत्न करती, हैं, हमारा दूरदर्शन मंत्रालय प्रयत्न करता हैं उस पर प्रभाव डालने के लिए क्या गीता कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट को आपने स्वीकार किया हैं? एक तो यह बात पूछनी हैं ।

दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कई सारे प्रस्ताव, कई निर्माताओं के कई सीरियल अभी तक पैंडिंग पड़े हैं, क्या उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई कमेटी बनाकर के कोई व्यवस्था की हैं या नहीं की हैं, जिससे कि आपके राजस्व पर कोई सकारात्मक असर पड़ सकें?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति महोदय, जहां तक पहले प्रश्न का उत्तर हैं, प्रश्न सं0 99 पर गीता कृष्णन कमेटी के संबंध में एक विस्तृत प्रश्न हैं, उसका उत्तर आलरेडी पटल पर हैं, जब वह आयेगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

दूसरा प्रश्न हैं। यह निर्णय सरकार नहीं करती हैं-इसके बारे में प्रसार भारती को निर्णय करना हैं। लेकिन हमने इस बात का आग्रह जरुर किया हैं कि सीरियल्स के संबंध में जितने भी प्रस्ताव आए हैं, उनका नियमों के अनुसार वस्तुपरक तरीके से जल्द से जल्द निष्पादन हो। साथ ही साथ सरकार ने यह भी निर्णय किया हैं कि उनसे कंर्टेट क्रिएशन के लिए उचित राशि ली जाये, ताकि दूरदर्शन के पास जो बड़े गुणी कलाकार हैं, उनका समुचित उपयोग हो। हमने इस साल 80 करोड़ रुपया दिया हैं और टेंथ प्लान में 500 करोड़ देने वाले हैं।

*88 [The questioner (Shri Anil Sharma) was absent. For answer *vide* pages 53-54].

अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु योजनाएं

*89 श्री मूल चन्द मीणा:
श्रीमती सरोज दुबे:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए चल रही परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और इन योजनाओं पर गत तीन वर्षो के दौरान राज्य-वार कितनी – कितनी राशि व्यय की गई हैं:

(ख) क्या सरकार को जनजातियों के विकास संबंधी योजनाओं हेतु निर्धारित निधियों के दुरुयोग के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन निधियों का दुरुयोग करने वाले राज्यों के नाम क्या-क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्त): (क) इस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के नाम इनके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को पिछले तीन वर्षो (1999-2000,2000-2001 और 2001-2002) के दौरान निर्मुक्त की गई राशि के ब्यौरे विवरण-I-II और III में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत धनराशि के दुरुपयोग के कुछ मामले इस मंत्रालय के ध्यान में आए हैं।

---

† सभा में यह प्रश्न श्रीमती सरोज दुबे द्वारा पूछा गया।